वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
अप्रैल, 2024 माह हेतु उपलब्धियां
*****

1. कैपेक्स लक्ष्य:

वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 7.77 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। चुनिंदा सीपीएसईज़ और अन्य सरकारी संगठनों के लिए बजट अनुमानित, जिनका कैपेक्स लक्ष्य 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानित कैपेक्स 7.41 करोड़ रुपये की तुलना में 4.86% अधिक है।

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

i. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) को शीर्ष समिति की सिफारिशों और माननीय मंत्री (वित्त) की मंजूरी के आधार पर, दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को नवरत्न का दर्जा दिया गया।
ii. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) को शीर्ष समिति की सिफारिशों और माननीय मंत्री (वित्त) की मंजूरी के आधार पर, दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को नवरत्न का दर्जा दिया गया।
iii. आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) को शीर्ष समिति की सिफारिशों और माननीय मंत्री (वित्त) की मंजूरी के आधार पर, दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को नवरत्न का दर्जा दिया गया था।
iv. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) को शीर्ष समिति की सिफारिशों और माननीय मंत्री (वित्त) की मंजूरी के आधार पर, दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को नवरत्न का दर्जा दिया गया था।
v. सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) के प्रारंभिक वर्गीकरण के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के प्रस्ताव पर दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को पीईएसबी के परामर्श से डीपीई द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

3. एनएलएमसी द्वारा सीपीएसईज़ की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण: -

i. विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की संपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में 242.88 करोड़ रुपए के संचयी लेन-देन मूल्य की चरण-I की ई-नीलामी के संबंध में वैकल्पिक तंत्र (एएम) से अनुमोदन प्राप्त हुआ था जिसमें ई-नीलामी के लिए प्रस्तुत किए गए कुल 130 भूखंडों/ब्लॉकों में से 72 भूखंडों/ब्लॉकों के लिए बोली लगाई गई थी।
ii. विभूति खंड, लखनऊ में स्थित बीएसएनएल संपत्ति के संबंध में, प्रक्रिया को रद्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाली 226 करोड़ प्लस ड्राप-डेड शुल्क को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, लखनऊ को उक्त संपत्ति के स्थानांतरण के लिए वैकल्पिक तंत्र (एएम) से अनुमोदन प्राप्त हुआ था।

4. सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 90 सीपीएसईज़ में से 10 के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापनों की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित की गई।

5. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल टिप्पणियां:

i. ऊर्जा के दुरुपयोग, अति प्रयोग और अकुशल उपयोग को कम करने की आवश्यकता के संदर्भ में, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, डीपीई और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन (ईएसएफ) ने दिनांक 25 अप्रैल, 2024 को 'एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन' पर एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया, जिसमें चुनिंदा महारत्न/नवरत्न सीपीएसईज़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ऊर्जा उपयोग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिनांक 25 अप्रैल, 2024 को डीपीई के कर्मचारियों के साथ एक संवेदीकरण बैठक भी आयोजित की गई थी। ये सत्र प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, आईआईटी, बॉम्बे द्वारा लिए गए थे।

ii. अप्रैल, 2024 माह में 01 सीएमसीडीसी बैठक में भाग लिया गया था।

6. सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ और जीईएम के माध्यम से खरीद:

i. **वर्ष 2023-24 (मार्च, 2024 तक) के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा एमएसई से खरीद अनिवार्य 25% (एमएसएमई-संबंध पोर्टल के अनुसार) के मुकाबले लगभग 35.73% थी।**

ii. **अप्रैल, 2024 (वित्तीय वर्ष 2024-25) तक जीईएम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद 53,405 करोड़ रुपये थी, जबकि अप्रैल, 2024 (वित्तीय वर्ष 2023-24) तक यह 6,270 करोड़ रुपये थी।**

7. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

सीपीएसईज़ द्वारा किए जाने वाले शीर्ष 30 सीएसआर व्यय ने वर्ष 2023-24 (मार्च, 2024 तक) के दौरान 3,660 करोड़ रुपये के सीएसआर व्यय की सूचना दी।

8. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 171 मामले रिपोर्ट किए गए/पंजीकृत किए गए। वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर 13 मामलों को खारिज कर दिया गया। 40 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 67 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समितियों के पास हैं। शेष 51 मामले जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास लंबित हैं।

*****